DIGICONTENT LIMITED
Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor) 18-20,
Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001, India
T: +9111 66561234 **F:** +911166561270
W: www.digicontent.co.in **E:** corporatedept@digicontent.co.in
CIN: L74999DL2017PLC322147

Ref: DCL/CS/160/2021

6th January, 2021

BSE Limited
P. J. Tower, Dalal Street
Mumbai- 400 001

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai- 400 051

Scrip Code: 542685

Trading Symbol: DGCONTENT

Dear Sirs,

Sub: Newspaper advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Re: Notice of Board Meeting to be held on 14th January, 2021 and intimation of closure of trading window

In furtherance to our letter dated 5th January, 2021, copies of advertisement of aforesaid notice published in "Hindustan" (Hindi) and "Mint" (English) newspapers on 6th January, 2021, are enclosed herewith.

This is for your information and records.

For **DIGICONTENT LIMITED**

(Vikas Prakash)
Company Secretary

आज का दिन 1919 में अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का निधन हुआ।

कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन

किफायती ऊर्जा से विकास को रफ्तार मिलेगी : मोदी

योजना

नई दिल्ली | एजेंसियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऊर्जा को लेकर सरकार का खाका साझा किया। इसके तहत उन्होंने ऊर्जा के उपभोग में स्वच्छ प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी दोगुनी से अधिक करने, ऊर्जा के स्रोतों को विविध बनाने, पूरे देश को एक गैस पाइपलाइन ग्रिड से जोड़ने और लोगों और उद्यमों को किफायती ईंधन मुहैया कराने का जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करते हुए कहा कि उनकी सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, विमानन, जल, डिजिटल और गैस संपर्क पर अभूतपूर्व काम कर रही है। ऊर्जा को लेकर योजना पर सरकार एकीकृत रुख अपना रही है। ऊर्जा का हमारा एजेंडा सर्व-समावेशी है। इस पाइपलाइन को 3000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है।

हाईब्रिड अक्षय ऊर्जा संयंत्र पर काम चल रहा : मोदी ने कहा, एक तरफ पांच-छह साल में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नेटवर्क को दोगुना कर करीब 32 हजार किलोमीटर का बनाया जा रहा है, दूसरी ओर गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा को मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े हाईब्रिड अक्षय ऊर्जा संयंत्र पर काम चल रहा है। आवागमन के इलेक्ट्रिक साधनों के साथ ही जैव ईंधन के विनिर्माण पर जोर दिया जा रहा है। मोदी ने कहा, 10 साल में गन्ना व अन्य कृषि उत्पादों से तैयार इथेनॉल करीब 20 प्रतिशत पेट्रोल का स्थानापन्न कर देगा। ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.2 से बढ़ाकर 15 फीसदी तक करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने परियोजना के पूरा होने की सराहना की : केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने जीएआईएल की कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के पूर्ण होने की सराहना करते हुए मंगलवार को कहा कि विभिन्न बाधाओं के कारण यह परियोजना रुक गई थी और इसे पूरा कराना उनकी सरकार का एक प्रमुख चुनावी वादा था।

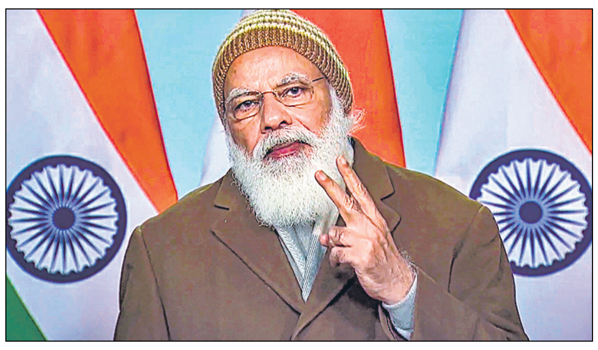
नई दिल्ली में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के उद्घाटन मौके पर बोलते प्रधानमंत्री मोदी। • प्रेट्र

किसानों को मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री ने कहा, ये पाइपलाइन क्यों जरूरी है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इससे दोनों राज्यों में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। उद्यमियों का खर्च कम होगा। कम खर्च में फर्टिलाइजर बन सकेंगे, किसानों को मदद मिलेगी। स्वच्छ ऊर्जा से प्रदूषण कम होगा, लोगों की सेहत अच्छी होगी।

700 सीएनजी स्टेशन खुलेंगे

मोदी ने कहा, वर्ष 2014 तक देश में सीएनजी स्टेशन 900 से ज्यादा नहीं थी, 6 साल में 1500 के करीब स्टेशन शुरू हुए। हम इसे 10 हजार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये गैस पाइपलाइन केरल-कर्नाटक में 700 सीएनजी स्टेशन खोलने में मदद करेगी। अब 25 की जगह 72 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंच रही है।

कोराना के कारण रद्द हुआ जॉनसन का दौरा

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी पूर्व निर्धारित यात्रा को स्थगित कर दिया। उन्होंने इसकी जानकारी फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी और खेद प्रकट किया।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन में कोविड के नए मामलों की वजह से पैदा हुए हालात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिटेन जल्द इस स्थिति से उबरने में सक्षम होगा। उन्होंने कोविड की मौजूदा स्थिति के बारे में जॉनसन की चिंताओं से अपनी सहमति और समझ जाहिर की। जॉनसन ने उम्मीद जताई कि वह निकट भविष्य में भारत की यात्रा कर पाएंगे। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की।

असाधारण परिस्थितिवश रद्द हुई यात्रा : सूत्रों ने कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा असाधारण परिस्थितिवश रद्द हुई है। ब्रिटेन नए कोविड के नए स्ट्रेन से जूझ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जॉनसन ने घरेलू स्थितियों से निपटने के लिए वहीं रहने का फैसला किया। ब्रिटेन ने विस्तृत रूप से ताजा हालात की जानकारी भी दी है। सूत्रों का कहना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा दोनों देशो के संबंधों के लिहाज से बहुत गई महत्वपूर्ण थी। लेकिन यात्रा रद्द होने से संबंधों की गर्मजोशी में कमी नही आएगी। दोनो देश संबंध सामान्य होने पर नए सिरे से कार्यक्रम पर विचार करेंगे।

बैकअप प्लान पर विचार

भारत गणतंत्र दिवस पर अपने बैकअप प्लान के मुताबिक, अतिथि को आमंत्रित करने पर विचार करेगा। फिलहाल विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट नही किया है कि गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जगह कौन मुख्य अतिथि हो सकते हैं।

लंबे समय बाद बने थे अतिथि

भारत में किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस पर लंबे समय बाद बुलाया गया था। आखिरी बार साल 1993 में ब्रिटेन के पीएम जॉन मेजर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे। जॉनसन के मुख्य अतिथि बनने पर भारत ने इसे नए युग की शुरुआत बताया था।

संक्षेप

एनडीए में कैडेटों की संख्या नहीं घटी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री ने बताया कि संस्थान में कैडेटों की संख्या में कमी नहीं आई है। पिछले साल के 144वें पाठ्यक्रम में कुल 389 कैडेटों ने दाखिला लिया। उनमें से 19 कैडेट मित्र देशों के हैं।

यात्रा निकालने की कोशिश में गिरफ्तार

अमरावती। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध रामतीर्थम पहाड़ी मंदिर में 28 दिसंबर को भगवान राम की प्रतिमा विरूपित किए जाने के विरोध में वहां यात्रा निकालने की कोशिश करने में मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सोमू वीरराजू सहित पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

थाई पूषम त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने मंगलवार को कहा कि भगवान मुरूग की पूजा के लिए समर्पित त्योहार थाई पूषम के लिए उन्होंने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश दिया है। लोगों ने उनसे थाई पूषम को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया था।

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

जयपुर। राजस्थान सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल में तीन जिला कलेक्टर सहित 21 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), 56 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), 28 भारतीय वन सेवा और 183 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं।

शादी के बंधन में बंधे अली अब्बास जफर

मुंबई। फिल्मकार अली अब्बास जफर शादी के बंधन में बंध गए हैं। अब्बास ने अपनी पत्नी एलिशिया जफर के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 1400 साल पहले इमाम अली ने फातिमा अल- जहरा से कहा था कि तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरे सारे दुख और दर्द गायब हो जाते हैं।

न्यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड का कल शुभारंभ होगा

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर

- न्यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड में डीएफसी के लिए नौ रेलवे स्टेशन
- डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी को भी प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्लूडीएफसी) के न्यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पश्चिमी डीएफसी में राष्ट्र को समर्पित किया जाने वाला यह पहला खंड है। इसकी कुल लंबाई 306 किलोमीटर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री दुनिया की पहली विद्युत मार्ग की डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 29 दिसंबर को पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा से न्यू भाऊपुर के बीच का खंड देश को समर्पित किया था। न्यू रेवाड़ी-न्यू मदार खंड का 79 किलोमीटर हरियाणा के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में है, जबकि शेष 227 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान के अजमेर, सीकर, नागपुर और अलवर जिलों से गुजरता है। इस खंड में नौ नए रेलवे स्टेशन हैं, जिन्हें डीएफसी के लिए बनाया गया है।

दुनिया में पहली बार दुमंजिला मालगाड़ी का परिचालन किया जा रहा है। इसका परीक्षण पूरा हो चुका है। इसकी क्षमता 25 टन एक्सेल लोड की है।

शहरों में आवास योजना का लक्ष्य इसी वर्ष पूरा होगा

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

तैयारी

- अक्तूबर तक सभी बेघर लोगों को छत मुहैया कराने के काम में तेजी
- अभी तक 112.2 लाख आवास की मांग, 109 लाख को मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सभी को आवास मुहैया कराने के साल 2022 के लक्ष्य को सरकार इसी साल पूरा करने की कोशिश कर रही है। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की इस योजना के तहत अभी तक के कुल 112.2 लाख आवास की मांग की तुलना में 109 लाख आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है। कोरोना प्रकोप से इसमें थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब फिर से तेजी आने लगी है।

मंत्रालय को उम्मीद है कि वह तय समय मार्च 2022 से पहले इस साल 2 अक्तूबर तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में देश के सभी शहरी गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए विशेष अभियान की घोषणा की थी। इसके तहत आजादी के 75 साल पूरे होने यानी साल 2022 तक का लक्ष्य तय किया गया था। अब तक 70.2 लाख से ज्यादा आवास दिए जा चुके हैं और 40.5 आवास पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार की लगातार कोशिश रही है कि राज्य अपने-अपने यहां से इस तरह के आवासों की सूची भेजें जिससे कि उनको जल्द से जल्द मंजूरी देकर पूरा कराया जा सके।

प्रधानमंत्री बोले-विश्व हमारा बाजार

नई दिल्ली | एजेंसी

भरोसा

- लिंक्डइन पर आत्मनिर्भर भारत के बारे में विचार साझा किए
- किफायती, टिकाऊ और उपयोगी वस्तुओं की खोज की जा रही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि दुनियाभर में किफायती, टिकाऊ और उपयोगी वस्तुओं की खोज की जा रही है। घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक विशाल बाजार प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे उत्पाद बनाना चाहता है, जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो और जिनकी विश्व स्तर पर तारीफ हो।

मोदी ने प्रोफेशनल सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन पर एक पोस्ट में सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में अपने विचार साझा किए और कहा कि इसमें गुणवत्ता पर उतना ही जोर है, जितना उत्पादन के पैमाने पर। उन्होंने कहा कि आज दुनिया हमारा बाजार है। भारत के लोगों में क्षमता है। एक राष्ट्र के रूप में दुनिया भारत को भरोसेमंद देश मानती है। अपने लोगों की योग्यता और देश के भरोसे के साथ भारत के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद दुनिया भर में पैठ बनाएंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सच्चा कदम होगा और वैश्विक समृद्धि को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने सोमवार को राष्ट्रीय माप-पद्धति सम्मेलन में अपने संबोधन की मुख्य बातों को भी साझा किया, जहां उन्होंने भारतीय उत्पादों के लिए मात्रा के साथ ही गुणवत्ता पर भी जोर दिया था। मोदी ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में कहा, भारत कौशल और प्रतिभा का एक ऊर्जा केंद्र है। हमारे स्टार्ट-अप उद्योग की सफलता हमारे युवाओं के उत्साह को दिखाती है। नए उत्पादों और सेवाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता मानकों के दोहरे सिद्धांत पर टिका हुआ है, और भारत अधिक उत्पादन करना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही वह ऐसे उत्पाद बनाना चाहता है, जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो।

मुखौटा कंपनी पर ईडी का शिकंजा

नई दिल्ली। ईडी ने आईएलएंडएफएस के कथित भुगतान संकट मामले में धनशोधन की जांच के दौरान सिंगापुर की एक संदिग्ध मुखौटा कंपनी की 452 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

संपत्ति को अस्थायी रूप से धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है। यह संपत्ति ब्रिटिश नागरिक जैमिन व्यास के स्वामित्व वाली 'एएस कोल पीटीई सिंगापुर' के हिस्सेदारी वाले शेयर के रूप में है। 'एएस कोल पीटीई सिंगापुर' के आईएलएफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड में 8.86 प्रतिशत शेयर हैं, जिनका वर्तमान मूल्य लगभग 452 करोड़ रुपये है। **(एजेंसी)**

नेपाल को तटबंध निर्माण पर आपत्ति

पिथौरागढ़ | वरिष्ठ संवाददाता

नेपाल ने धारचूला में भारतीय क्षेत्र में काली नदी किनारे किए चल रहे तटबंध निर्माण पर आपत्ति जताई है। नेपाल के दार्चूला के जिल्लाधिकारी ने इस संबंध में अपने देश के गृह विभाग को पत्र भेजा है।

भारत और नेपाल के बीच जिले में 170 किमी से अधिक दूरी तक काली नदी दोनों देशों के बीच सीमा विभाजन करती है। वर्ष 2013 की आपदा में काली नदी ने यहां कहर बरपाया था। इससे धारचूला, जौलजीबी, बलुवाकोट में नदी किनारे के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ और दोनों तरफ करीब 80 घर बह गए थे। इस आपदा में भारतीय क्षेत्र के तवाघाट ऐलागाड़, बलुवाकोट, छारछुम, गोठी, कालिका, जौलजीबी में 56 से अधिक मकानों के साथ 18 से अधिक पैदल पुल और धारचूला में कई किमी एनएच नदी में बह गया था। नेपाल ने इसके बाद अपनी तरफ नदी से हो रहे भूकटाव को रोकने के लिए 5 किमी क्षेत्र में मेगा प्रोजेक्ट के तहत तटबंध का निर्माण 6 साल पहले ही कर लिया है। भारतीय क्षेत्र में इन दिनों 2 करोड़ 76 लाख की लागत से सिंचाई विभाग काली नदी किनारे तटबंध बना रहा है। नेपाल के महाकाली नदी नियंत्रण आयोजना खलंगा के निर्देशक शोभाकर पौडेल ने इस संबंध में विस्तृत पत्र नेपाला प्रशासन को अपनी आपत्ति के साथ भेजा है।

सीमा पर सख्ती को लेकर एसएसबी के खिलाफ प्रदर्शन

सोनौली (महराजगंज)। नेपाल सीमा पर पैदल आवाजाही और घरेलू सामान पर भी सख्ती पर मंगलवार को सोनौली में एसएसबी के खिलाफ व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा। व्यापारियों ने एसएसबी पर ज्यादती का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों की भीड़ में एसएसबी के डॉग स्क्वायड के कुत्तों के पहुंच जाने से भगदड़ की स्थिति भी बन गई। पुलिस ने व्यापारियों को समझा-बुझाकर शांत किया।

खड़से मामले में दस्तावेज मांगे

पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता एकनाथ खड़से के खिलाफ भोसारी स्थित जमीन मामले में भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अंजलि दमानिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने मंगलवार को दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे हैं।

ईडी ने हाल ही में पूर्व भाजपा नेता खड़से को मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था लेकिन खराब सेहत और कोरोना वायरस संक्रमण का संदेह जताये जाने के बाद उन्हें पेश होने के लिए और वक्त दिया गया। शहर के वकील असीम सरोदे ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने कुछ दिन पहले उनसे संपर्क किया था। **एजेंसी**

फर्जी पत्र में विदेशी गवाह से पूछताछ की इजाजत मांगी

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

सीबीआई ने वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर कथित तौर पर फर्जी पत्र लिखे जाने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर और हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा से जुड़े मामले में मंगलवार को उच्च न्यायालय से गवाह के तौर पर एक विदेशी नागरिक से पूछताछ करने की इजाजत मांगी।

निचली अदालत के 23 अक्तूबर 2020 को विदेशी नागरिक सी एडमंड एलेन को तलब करने की सीबीआई की मांग खारिज कर दी थी। इस मामले में वर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने सीबीआई की मांग का इस आधार पर विरोध किया था कि पहले भी गवाह को चार बार पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन वह अदालत नहीं पहुंचा। जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए एक साल का वक्त तय किया था। यह समयसीमा भी समाप्त हो गई है। पूछताछ की इजाजत देने से सुनवाई नए सिरे से शुरू हो जाएगी। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता अनिल ग्रोवर ने कहा, एलेन पूछताछ को तैयार हैं।

बंगाल में एक और मंत्री का इस्तीफा

मिशन बंगाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के युवा और खेल मामलों के राज्यमंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य सचिवालय के सूत्रों ने इस बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि शुक्ला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और उन्होंने इसकी एक प्रति राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी भेजी है। क्रिकेटर रह चुके शुक्ला के इस्तीफा के पहले राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की रणजी टीम के पूर्व कप्तान और हावड़ा (उत्तर) के विधायक शुक्ला (39) ने बनर्जी को भेजे अपने त्यागपत्र में कहा है कि वह राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। हालांकि, शुक्ला से कोई जवाब नहीं मिल पाया।

कोलकाता में 'द्वारे सरकार' अभियान के तहत मंगलवार को 'स्वास्थ्य साथी कार्ड' लेने के लिए कतार में खड़ीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। • प्रेट्र

वाड्रा से लगातार दूसरे दिन पूछताछ

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति विरोधी कानून के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच के सिलसिले में मंगलवार को उनसे लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

52 वर्षीय वाड्रा ने मंगलवार को फिर कहा कि इस पूछताछ का मकसद किसानों के आंदोलन जैसे देश से जुड़े वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना है। वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति हैं। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग के चंडीगढ़ जांच इकाई का एक दल मंगलवार दिन में करीब तीन बजे वाड्रा के सुखदेव विहार स्थित कार्यालय पहुंचा और वहां से शाम छह बजे के बाद निकला। **एजेंसी**

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारत सरकार द्वारा 08 जनवरी 2021 को ₹27,000 करोड़ के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री की घोषणा

भारत सरकार ने चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है :

क्र. सं.	प्रतिभूतियों के नाम	अधिसूचित राशि सांकेतिक (₹ करोड़ में)	खुदरा निवेशकों के लिए निर्धारित* (₹ करोड़ में)
1.	3.96% सरकारी स्टॉक 2022	2,000	100
2.	5.15% सरकारी स्टॉक 2025	11,000	550
3.	5.85% सरकारी स्टॉक 2030	8,000	400
4.	6.80% सरकारी स्टॉक 2060	6,000	300

भारत सरकार के पास उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रत्येक प्रतिभूति के सापेक्ष ₹2000 करोड़ तक का अतिरिक्त अभिदान रखने का विकल्प होगा।

यह बिक्री इस अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना') कहा गया है। यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 में, भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ.स.4(2)- डब्लू एंड एम/2018 में निर्दिष्ट नियम और शर्तों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

ये नीलामिया **मूल्य आधारित होगी और एकाधिक मूल्य पद्धति** का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा **08 जनवरी 2021 (शुक्रवार)** को आयोजित की जाएंगी। इन नीलामियों के परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे और सफल बोलीकर्ताओं को **11 जनवरी 2021 (सोमवार)** को भुगतान करना होगा।

कृपया विस्तृत विवरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट- (**www.rbi.org.in**) पर **04 जनवरी 2021** की भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी देखें।

खुदरा निवेशक ध्यान दें*

(*भविष्यि निधियां, न्यास, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, कंपनियां, हिंदू अविभक्त परिवार तथा अलग-अलग व्यक्ति)

खुदरा निवेशक किसी बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी के माध्यम से उनके लिए निर्धारित राशि हेतु गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर नीलामियों में हिस्सा ले सकते हैं। अधिक जानकारी, प्राथमिक व्यापारियों/बैंक शाखाओं की विस्तृत सूची और टेलीफोन नंबरों तथा आवेदन फॉर्मों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (**www.rbi.org.in**) या फिम्डा की वेबसाइट (**www.fimmda.org**) देखें।

सरकारी प्रतिभूतियां सुरक्षा, चलनिधि तथा दीर्घ अवधि के लिए आकर्षक प्रतिफल प्रदान करती हैं।

''पैसे का वादा करने वाले ई-मेल/एसएमएस/टेलीफोन द्वारा धोखा न खाएं''

बदायूं में निर्भया जैसी दरिंदगी

शर्मनाक

उघैती(बदायूं) | हिन्दुस्तान टीम

हैवानियत

- दरिंदों ने महिला के शरीर में रॉड डाली, पसली और पैर तोड़े
- महंत व उसके चेलों ने महिला से गैंगरेप के बाद की नृशंस हत्या

उघैती में पूजा करने गई 50 वर्षीय महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। पूरे घटनाक्रम में हैवानियत की इंतहा यह रही कि महिला के शरीर में रॉड डालने के साथ ही उसकी बायीं पसली, बायां पैर और बायां फेफड़ा भी वजनदार प्रहार से फाड़ दिया गया।

महिला की मौत की वजह अधिक रक्तस्राव व सदमा लगने से होना सामने आई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में मंदिर के महंत समेत उसके एक चेले व ड्राइवर के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा कायम किया है। दरिंदगी को अंजाम देने वाले शातिर तीसरे दिन भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मानवीयता को झकझोरने वाली यह सनसनीखेज वारदात उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव की है।

यहां रहने वाली एक महिला पास के गांव स्थित एक मंदिर पर नियमित जाती थी। रविवार को भी महिला गई थी। मुकदमे के मुताबिक देर रात मंदिर का महंत अपनी बोलेरो से उसका शव घर के दरवाजे पर फेंककर चला गया। बताया जाता है कि इससे पहले आरोपी महंत उसे अपनी गाड़ी से इलाज के लिए चंदौसी भी ले गया था। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया लेकिन उघैती के थानेदार रावेंद्र प्रताप सिंह ने परिजनों की फरियाद सुनना तो दूर घटनास्थल का मौका मुआयना तक नहीं किया। वहीं सोमवार दोपहर 18 घंटे बाद लाश पोस्टमार्टम को भेजी।

महिला डॉक्टर समेत तीन डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शाम को आयी तो प्राइवेट पार्ट में गंभीर इंजरी निकली। काफी ब्लड भी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख अफसर भी हैरत में हैं। वहीं बाबा सत्यनारायण, उसका चेला वेदराम व ड्राइवर जसपाल के खिलाफ सामूहिक रेप के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया।

एनडीआरएफ की महिला टीम तैनात

नई दिल्ली। देश के संघीय आपदा बल एनडीआरएफ में सौ से अधिक महिला लड़ाकों एवं बचावकर्मियों के पहले जत्थे को शामिल किया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की प्रशिक्षित महिलाओं की पहली टीम को हाल ही में उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर शहर में गंगा नदी के किनारे आपात सेवाओं में तैनात किया गया है।

एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा, महिलाओं की पहली बचाव टीम तैनात है। हाल ही में यूपी सरकार ने एनडीआरएफ की एक टीम भेजने का आग्रह किया था और वे (महिलाएं) वहां (गढ़मुक्तेश्वर) गईं।

DIGICONTENT LIMITED
CIN: L74999DL2017PLC322147
Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor)
18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001
Tel: +91-11- 6656 1234 Fax: +91-11- 6656 1270
Website: www.digicontent.co.in E-mail: investor@digicontent.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Digicontent Limited will be held on Thursday, the 14th January, 2021, to, inter-alia, consider and approve the Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and nine months period ended on 31st December, 2020. Investors may visit the websites of the Company viz. **www.digicontent.co.in** and the Stock Exchanges viz. **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** for further details in this regard.

Further, in terms of Company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons", the trading window for trading in the equity shares of the Company is closed **from Saturday, the 19th December, 2020 till Saturday, the 16th January, 2021** (both days inclusive).

For **Digicontent Limited**
Sd/-
(Vikas Prakash)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 5th January, 2021

Sale of SAIL's units may not fill Centre's coffers

Strategic offloading of stake will not add to govt's FY21 divestment receipts

Asit Ranjan Mishra
asit.m@livemint.com
NEW DELHI

The sale proceeds from SAIL's Salem and Bhadravati steel plants will go directly to the state-run steelmaker as the two plants are its subsidiaries.

A planned strategic sale of two Steel Authority of India Ltd (SAIL) plants expected to be completed by 31 March will not add to the government's divestment receipts for this fiscal, a finance ministry official said on Tuesday, requesting anonymity.

The sale proceeds will instead go directly to the state-run steelmaker as the two plants are its subsidiaries, the official said, adding that this is despite the Department of Investment and Public Asset Management (Dipam) handling the disinvestment process.

The finance ministry is hopeful of completing the strategic sale of SAIL's Salem (Tamil Nadu) and Bhadravati (Karnataka) steel plants in this fiscal through March, the official said.

"Alternative mechanism for disinvestment headed by home minister Amit Shah has cleared the business transfer agreement (of SAIL's plants) that will be shared with qualified bidders and their comments will be sought. In this case, the financial bids may come before March, but security clearance, competition commission clearance may take some time depending on who qualifies. We are still hopeful of the transaction getting completed in FY21. We are keeping our fingers crossed," the official said.

Dipam had on 4 July 2019 sought expressions of interest in the sale of the two plants.

It had appointed SBI Capital Markets Ltd as the transaction adviser following an in-principle approval from the Cabinet Committee on Economic Affairs for strategic disinvestment of several state-run companies.

If successful, this would be the first strategic disinvestment of this fiscal. *Mint* had reported on 24 December that privatization of Bharat Petroleum Corp. Ltd (BPCL) may spill over to the next fiscal.

DIVESTMENT GOAL AT STAKE

IF successful, SAIL plant sales would be the first strategic disinvestment of the fiscal year 2021

THE finance ministry is likely to miss the FY21 divestment target again due to covid-led slowdown

SO far this year, the govt has garnered ₹12,225 crore through minority stake sales and initial share sales

Strategic disinvestment of BPCL was crucial for the government to achieve its disinvestment target of ₹2.1 trillion for FY21 as the sale of India's second-largest fuel retailer is expected to fetch the government at least ₹45,000 crore. So far this year, the government has garnered ₹12,225 crore through minority stake sales and initial share sales of Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.

While the finance ministry had missed the disinvestment target of ₹65,000 crore for FY20 by ₹14,701 crore, it is likely to miss the target again due to the covid induced economic downturn

SAIL owns and operates five integrated steel plants at Bhilai, Bokaro, Durgapur, Rourkela and the IISCO Steel Plant in Asansol. It also owns the Chandrapur ferro alloys plant and three special steel plants: Alloy Steels Plant (at Durgapur in West Bengal), Salem Steel Plant (in Tamil Nadu) and Visvesvaraya Iron and Steel Plant (at Bhadravati in Karnataka).

Sail recorded total revenue from operations of ₹61,025 crore in FY20.

World Bank signs $105 million project to boost water transport in West Bengal
bit.ly/2XbXGKI

Large steel players increase market share amid continuous price hikes

Tanya Thomas
tanya.t@livemint.com
MUMBAI

With demand from user industries recovering, steel buyers have been forced to absorb the higher cost. MINT

The large steel mills of the country are expected to report decadal-high profits and a large increase in market share in the second half of the fiscal, given that repeated price hikes are doing little to dent domestic demand for the metal.

Producers have hiked steel prices several times in the past 15 weeks, but with demand from user industries such as auto and construction recovering, buyers have been forced to absorb the higher cost.

Indian steel prices move in tandem with the global average, which is influenced by Chinese demand. The Chinese government's $550 billion stimulus to revive its economy has increased the nation's appetite for steel at a time when steel exporting countries such as Japan and South Korea have curtailed production. This mismatch in demand and supply has sent global steel prices rocketing.

"Globally, steel prices are likely to stay firm as China is not expected to export large volumes due to better balance in their domestic market and there are no other significant exporters in the world market. Given all of this, we believe that the steel demand in the country should grow at least at the rate of gross domestic product (GDP) growth or higher in FY22. Typically, this is the trend in a developing country, though traditionally in India steel demand has been lower than the GDP growth rate," Tata Steel managing director and chief executive officer T.V. Narendran said.

Indian steel prices have always been pegged just marginally below that of imported steel and steel mills have been able to increase prices in keeping with the global trend, allowing them to make profits. However, this advantage appears to apply only to large integrated players who have their own iron ore supply and comes at the cost of smaller steel producers.

Historically, Indian steel production has been split more or less evenly between the large integrated players, such as Tata Steel, SAIL and JSW Steel, and smaller secondary steelmakers. However, with covid forcing out many marginal producers out of the market, the larger players have gained a bigger piece of the pie.

The top six steel producers increased their market share in crude steel production to 65% in December, against a historical average of 55% while their capacity utilization has risen to 85% against an average of 78% until then while that of secondary players fell to 65%, according to credit ratings agency ICRA. "These trends indicate the rising dominance of large steel players in the domestic industry and an adverse impact of pandemic on the business performance of some smaller steel producers, which would find it difficult to operate at pre-covid levels in the near term," ICRA said.

Karan Bajwa to lead Google Cloud in APAC

Nandita Mathur
nandita.m@livemint.com
NEW DELHI

Karan Bajwa, who heads Google Cloud in India, will lead the internet search giant's cloud initiatives for the Asia-Pacific, the company said in a statement on Tuesday.

Bajwa will lead all regional revenue and go-to-market operations for Google Cloud, including on Google Cloud Platform (GCP) and Google Workspace starting Tuesday. Bajwa succeeds Rick Harshman who leaves the organization for a new opportunity. Currently based in Gurugram, Bajwa will relocate to Singapore. He also continues to lead Google Cloud in India until a new senior leader for the business is appointed. He will report to Rob Enslin, president of sales, Google Cloud, the company said.

Bajwa will continue to lead Google Cloud in India until a new senior business leader is appointed

"Since Karan joined us in March 2020, Google Cloud in India has grown from strength to strength. He has advanced the digital transformation journeys of many large Indian organizations across industries and successfully expanded our partner community. He brings tremendous management and sales experience with him to this regional role, and we're thrilled to have him at the helm of our APAC business," said Enslin.

"With the disruptions of 2020 behind us, a true test of 2021 will be how companies replatform and build on the cloud not only for resilience but agility and innovation, and I'm excited for the opportunity to lead Google Cloud's business in APAC to maximize this next phase of growth," said Bajwa.

NYSE scraps plans to delist 3 Chinese state-owned telcos

AP
feedback@livemint.com
BEIJING

The NYSE made a U-turn after talking to regulators. BLOOMBERG

The New York Stock Exchange has scrapped plans to remove shares of three Chinese state-owned phone carriers under an order by US President Donald Trump that Beijing warned might lead to retaliation.

The exchange cited "further consultation" with regulators but its announcement late Monday gave no other details.

China's foreign ministry on Tuesday criticized Washington for "suppressing foreign companies" but made no direct comment on the NYSE announcement.

The NYSE said on Thursday it would remove China Telecom Corp., China Mobile and China Unicom Hong Kong under Trump's November order barring Americans from investing in securities issued by companies deemed to be linked to the Chinese military.

The order added to mounting US-Chinese tension over technology, security and spying accusations.

Trump's order in Nov had barred Americans from investing in securities issued by firms linked to Chinese military

The Trump administration has imposed export controls and other sanctions on some Chinese companies, visa curbs on members of the ruling Communist Party and other restrictions.

"The suppression will have very limited impact on Chinese companies, but it will damage the national interest and image of the US," said foreign ministry spokeswoman Han Chunying. She expressed hope Washington will "do more to maintain the order of the global financial market" and protect investors.

Political analysts expect little change in policy under President-elect Joseph Biden, who takes office on 20 January, due to widespread frustration with China's trade and human rights records and accusations of spying and technology theft.

Trump's November order bars Americans from investing in securities issued by companies deemed to be part of efforts to modernize the Communist Party's military wing, the People's Liberation Army.

The PLA is one of the biggest and most heavily-armed militaries. It is spending heavily to develop nuclear submarines, stealth fighters, ballistic missiles and other advanced weapons.

The Pentagon has added 35 companies to its blacklist. In addition to the phone carriers, they include telecom equipment giant Huawei, China's biggest maker of processor chips, three state-owned oil producers and construction, aerospace, rocketry, shipbuilding and nuclear power equipment companies.

Hong Kong-traded shares in the three phone carriers surged Tuesday. China Telecom rose 3.4%, China Mobile jumped 5.7% and China Unicom surged 8.5%.

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
WBSETCL
Registered Office: Vidyut Bhavan, DJ Block, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700 091
CIN: U40101WB2007SGC113474 • web: www.wbsetcl.in
NIT No.: CE/ (O&M) – II/KALNA TR. BAY/2020-21/11 Date: 31.12.2020
The **Chief Engineer (O&M)-II** invites e-Tender for "Construction of Two Nos. 33/11 KV Transformer Bay and installation of 11 Nos. 12 KV VCB Switchgear Panel with extension of 11 KV Switchgear Room at Kalna 132 KV Sub Station and allied work on Turn Key basis." Bid submission start date (online): **14.01.2021** from **09:00 A.M.** Closing date (online): **27.01.2021** at **03.00 P.M.** Interested bidders may visit the following websites for details: -**https://wbtenders.gov.in, https://etender.wb.nic.in** and **http://www.wbsetcl.in.**
ICA-T0209(1)/2021

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
Office of The Executive Engineer (Special Project) Rohini
Sub-zonal Office Building,
3rd Floor, Sector-17, Rohini, Delhi
No. EE(Sp.Pr.) RZ/NDMC/2020-21/ 844 **Dated: 04.01.2021**
CORRIGENDUM
The dates in NIT no. EE(SpPr)RZ/TC/2020-2021/03 dated 04.11.2020 for 'Empanelment for the work of hiring of waste segregating trommels, machinery required for feeding to trommel from dumpsite to trommel site and for creating stacks of bio-mined output i.e. inert, RDF and C&D Waste for bio-mining & bio-remediation work at Bhalswa, Ghazipur & Okhla dumpsites' are rescheduled as under:
Last date of Registration with IT Department of North DMC — 14.01.2021 upto 15:00 hours
Last date for downloading of tender document — 14.01.2021 upto 17:00 hours
Submission of Bids — 15.01.2021 upto 15:00 hours
Opening of Technical Bid — 15.01.2021 at 15:15 hours
Opening of Financial Bid — To be intimated separately
All other terms & conditions of the NIT will remain same.
RO No. 49/DPI/North/2020-21 **Executive Engineer, (Special Project)**

New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida, (U.P.)
Website: www.noidaauthorityonline.com
E-TENDER NOTICE
E-Tenders are invited from firms / contractors registered with UPLC Lucknow for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on NOIDA Authority's official Website: **www.noidaauthorityonline.in** and **https://etender.up.nic.in.** Please ensure to see these websites for any changes/amendments & corrigendum etc.
1 **Job No.: 01/FC/Consultant/2020-21**, **Name of Work**- RFP for Selection of Consultant for Costing Accounting for NOIDA.
Which can be uploaded by **date 05.02.2021** upto 5.00 pm. Pre-qualification shall be opened/downloaded on **date 08.02.2021** at 11.00 am.
Manager (System)
CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

BSES Rajdhani Power Limited, New Delhi
TENDER NOTICE **Date: 06.01.2021**
Sealed tenders under two Bid System (Unpriced & Priced) is invited for following job from all bidders.

NIT No.	Brief Item Description	Estimated Cost (₹)	Cost of EMD (₹)	Due Date & Time of Submission	Date & Time of Opening
CMC/BR/20-21/ SV/AR/889	REPAIRING OF ONE NO. 40 MVA, 66/11KV POWER TRANSFORMER ATAEROCITY GRID IN BRPL.	97 Lacs	1.94 Lacs	27.01.2021 15:45 HRS	27.01.2021 16:00 HRS

Cost of each Tender Document : ₹ 1180/- (Including GST)
For details in respect of Equipment/BOM/Services, Qualifying requirements, Terms & conditions, purchase/submission of tender documents etc. please visit our website **www.bsesdelhi.com**
Head (Contracts & Materials)
Regd. Off. : BSES Rajdhani Power Limited, BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi-110019 I Corporate Identification No.: U40109DL2001PLC111527
Telephone No. : +91 11 3999 7235 I E-mail : brpl.eauction@relianceada.com I Website : www.bsesdelhi.com

एम एस टी सी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
MSTC LIMITED (A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)
CIN: L27320WB1964GOI026211
NIT for : **"RENEWAL OF EXISTING IBM SOFTWARE LICENSES & SUPPORT INSTALLED ON MSTC SERVER INFRASTRUCTURE FOR ONE (1) / THREE (3) YEARS" - e-Tender No. MSTC/ Head Office/Systems/5/20-21/ ET/20.** Please Log on to **www.mstcindia.co.in** for detail. All future Corrigendum / Addendums / Time Extension will be published in the website only. Bidders should regularly visit above website to keep themselves updated, for amendments, if any.
HAR EK KAAM DESH KE NAAM

NPCIL
रावतभाटा राजस्थान साईटई.ओ.आई. आमंत्रण
संख्या.आरआरसाईट/सीएसआर/2020-21/5
एन.पी.सी.आई.एल., आर.आर.साईट 15 माह की अवधि के लिए सी.एस.आर. के अंतर्गतमहिलायों के लिये सिलाई के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्ट और स्वायत्त संगठन आदि से ई.ओ.आई. आमंत्रित करती है। परियोजना की अनुमानित लागत रुपये 68,37,338 /-(अड़सठ लाख सैंतीस हजार तीन सौ अड़तीस) है ।उपरोक्त क्षेत्र में अनुभव रखने वाले इच्छुक पक्ष www.npcil.nic.in से दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं या अधोहस्ताक्षरी से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है ।प्रस्ताव 22.01.2021 को 11 बजे तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।संबंधित व्यक्ति :संजय कांडपाल, प्रोजेक्ट प्रभारी, आरआरसाइट।ईमेल - skandpal@npcil.co.in मोबाइल: 9413358039

DIGICONTENT LIMITED
CIN: L74999DL2017PLC322147
Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor)
18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001
Tel: +91-11- 6656 1234 **Fax:** +91-11- 6656 1270
Website: www.digicontent.co.in **E-mail:** investor@digicontent.co.in
NOTICE
NOTICE is hereby given that pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Digicontent Limited will be held on Thursday, the 14th January, 2021, to, inter-alia, consider and approve the Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and nine months period ended on 31st December, 2020. Investors may visit the websites of the Company viz. **www.digicontent.co.in** and the Stock Exchanges viz. **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** for further details in this regard.
Further, in terms of Company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons", the trading window for trading in the equity shares of the Company is closed **from Saturday, the 19th December, 2020 till Saturday, the 16th January, 2021** (both days inclusive).
For **Digicontent Limited**
Sd/-
(Vikas Prakash)
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: 5th January, 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in
Auction of Government of India Dated Securities for ₹27,000 crores on January 08, 2021
Government of India (GOI) has announced the sale (re-issue) of four dated securities:

Sr. No.	Nomenclature	Notified amount Nominal (in ₹ Crore)	Earmarked for Retail Investors* (in ₹ Crore)
1	3.96% GS 2022	2,000	100
2	5.15% GS 2025	11,000	550
3	5.85% GS 2030	8,000	400
4	6.80% GS 2060	6,000	300

Government of India will have the option to retain additional subscription up to ₹2,000 crores against each security mentioned above.
The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification'). The stocks will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400001, as per the terms and conditions specified in the General Notification F.No.4(2)-W&M/2018, dated March 27, 2018.
The auction will be **price based** for all the four securities, using **multiple price method.** The auction will be conducted by RBI, Mumbai Office, Fort, Mumbai on **January 08, 2021 (Friday)**. The result will be announced on the same day and payment by successful bidders will have to be made on **January 11, 2021 (Monday)**.
For further details, please see RBI press release dated **January 04, 2021** on RBI website - (**www.rbi.org.in**).
Attention Retail Investors*
(*PFs, Trusts, RRBs, Cooperative Banks, NBFCs, Corporates, HUFs and Individuals)
Retail investors can participate in the auctions for the amounts earmarked for them on a non-competitive basis through a bank or a primary dealer. For more information, detailed list and telephone numbers of primary dealers/bank branches and application forms please visit RBI website (**www.rbi.org.in**) or FIMMDA website (**www.fimmda.org**).
Government Stock offers safety, liquidity and attractive returns for long duration.
"Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money"

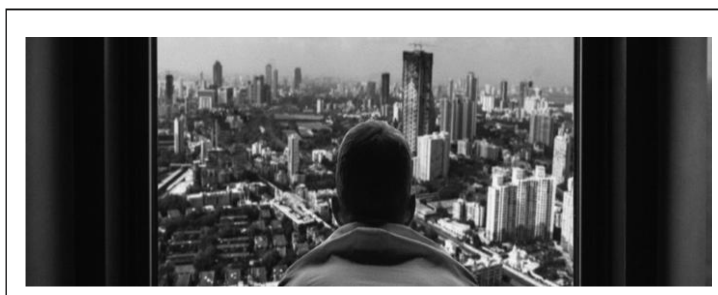
Growth is
not just about business.
It's also about the business of life.
Growth is...On.
mint Think *Ahead.* Think *Growth.*
Follow us: mint.live livemint live_mint livemint www.livemint.com